>

Title: Need to impose restriction on import of dairy products from Australia and Newzealand.

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : महोदय, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी इकनॉमिक रिसेशन के कारण न्यूज़ीलैंड, आस्ट्रेलिया व अन्य कई विदेशी मुल्क बड़ी मात्रा में डेयरी उत्पाद सस्ती दरों पर भारत में डंप कर रहे हैं। ड्राई मिल्क, मिल्क पावडर व डेयरी प्रोडक्ट के बटर ऑयल आयात से स्वदेशी उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा जिसका सीधा प्रभाव गांवों के गरीब दूध उत्पादकों पर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश के किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन व दुग्ध उत्पादन का धंधा करते हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि देश के डेयरी उत्पादकों के संगठन ने कल से दूध खरीद को बंद करने का ऐलान किया हुआ है। देश भर में दूध उत्पादक लगभग 60 लाख लीटर दूध रोजाना खरीदते हैं। पशुपालकों से दूध की खरीद बंद होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर इस आयात से भारतीय कंपनियों का टिकना मुश्किल होगा। मेरी सरकार से मांग है कि देशी उद्योगों व डेयरी किसानों को पनपाने के लिए आयात बंद करें अथवा आयात शुल्क में बढ़ोतरी करे।[r85]

MR. CHAIRMAN : Dr. C. Krishnan, your matter has already been recorded under Rule 377. Therefore, you do not have to speak it again.

DR. C. KRISHNAN (POLLACHI): Yes, Sir, I agree with you.

MR. CHAIRMAN: It has already been recorded.

DR. C. KRISHNAN : Okay, Sir. Thank you, I am not raising it again.

SHRIMATI P. SATHEEDEVI : Sir, please allow me to raise my matter.

MR. CHAIRMAN: Madam, your matter is totally a State matter.

SHRIMATI P. SATHEEDEVI : No, Sir. It is not a State matter. It is an urgent matter. It is concerning violation of gender rights. Young women and girls are being attacked...(*Interruptions*)

DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Sir, even if it is not a State matter, it should be allowed to be raised here. Many Members have been raising the State matters in the House.

MR. CHAIRMAN: No. You cannot make such types of remarks.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Madam, you may speak for only one minute.